www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 209 | जौनपुर मंगलवार, 17 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

छात्रों की शिष्टाचार मुलाकात सीएम साय ने दी बधाई

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल , रायपुर के छात्रों ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की मिलिट्री पाइप बैंड प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि आपकी इस उपलब्धि से न केवल आपके विद्यालय, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह राज्य के लिए गर्व का विषय और एक बड़ी उपलब्धि है।इस अवसर पर स्कूल के संचालक सिद्धार्थ सिंह, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) कर्नल आर.के. वर्मा सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मिलिट्री पाइप बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर के सैनिक स्कूल भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार द ग्रेट इंडिया सैनिक स्कूल, रायपुर ने इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता जिला स्तर से प्रारंभ होकर राज्य स्तरीय, जोन स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित की जाती है। छत्तीसगढ़ दक्षिण जोन का हिस्सा है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के सैनिक स्कूल शामिल होते हैं।

माकपा ने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए 86 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के तहत चुनाव लड़ रही पार्टी ने अधिकांश सीटों पर मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है।घोषित सूची में 56 वर्तमान विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व ने अनुभवी नेताओं पर भरोसा कायम रखा है, हालांकि कुछ सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन एक बार फिर कन्नूर जिले की धर्मदम सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में वह पार्टी के एकमात्र पोलित ब्यूरो सदस्य हैं जो चुनाव मैदान में हैं। मौजूदा सरकार के कई मंत्रियों को भी उनके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें पी.ए. मोहम्मद रियास (बेयपोर), वी. शिवनकुट्टी (नेमम), के.एन. बालगोपाल (कोट्टारक्करा), वीना जॉर्ज (अरनमुला), वी.एन. वासवन (एट्टुमनूर), ओ.आर. केलु (मनंथवाडी) और साजी चेरियन (चेंगन्नूर) शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची में कुछ प्रमुख नेताओं के नाम शामिल नहीं होने से भी चर्चा हुई है।

ओडिशा एससीबी अस्पताल अग्निकांड- पीएम मोदी ने पीड़ितों के लिए सहायता की घोषणा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 10 मरीजों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पीएम ने मृतक के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पीएम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने घोषणा की कि पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता के

तौर पर प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, ष्ओडिशा के कटक स्थित एक अस्पताल में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी मृतकों के परिवारों के लिए राहत की घोषणा की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। घायलों के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद तुरंत प्रभावित परिवारों और अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया और राहत कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। रविवार–सोमवार की रात 2रू30 बजे अचानक एससीबी अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आगजनी में अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों की जान चली गई।

बिहार में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू, पांचवीं सीट पर सियासी दावे

पटना, (एजेंसी)। बिहार से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए यहां मतदान सोमवार सुबह नौ बजे शुरू हुआ। विधानसभा परिसर में सुबह से ही मतदान के लिए विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार में राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए गहमागहमी बनी हुई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सहित कई मंत्री और विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं। महागठबंधन के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी विधानसभा पहुंच गए। एआईएमआईएम ने रविवार को ही महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। बिहार में एनडीए की बात करें तो उसने इस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार और पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है जबकि राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

बिहार के राज्यसभा सदस्य जिनका कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा एवं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं।

नाव आयोग ने सरकार से बाद ट्रांसफर किए पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)।चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन पुलिस अधिकारियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिनके ट्रांसफर के आदेश अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख (28 फरवरी) के बाद जारी किए गए थे। इस रिपोर्ट में उन मामलों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें 'तार्किक विसंगति' श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने के बाद चल रहे न्यायिक निर्णय के लिए भेजा गया था। अतिरिक्त

मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से चुनावों के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून) और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट भी मांगी है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार को भेजे गए एक अन्य पत्र में, चुनाव आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों का विवरण भी मांगा है जिनके अधिकार क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनाव संबंधी हिंसा की घटनाएं घटी थीं। चुनाव आयोग ने दूसरे पत्र में लिखा है कि उपरोक्त ज्ञापन और उसके उत्तर के क्रम में, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप उन पुलिस स्टेशन–स्तर के अधिकारियों की एक और सूची दें, जिनके अधिकार क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनावों में मतदान से पहले और मतदान के दिन हिंसा की घटनाएं घटी थीं। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान से पहले, मतदान दिन और मतदान के बाद हिंसा की घटनाएं घटी थीं।

विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं - जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित अल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस ''अनस्टॉपेबल भारत 2026'' में एक अनौपचारिक चर्चा सत्र के दौरान बोलते हुए कहा कि भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सरकार नवाचार को प्रारंभिक चरण से ही बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई पहलों का उल्लेख किया और कहा कि विज्ञान ज्योति जैसे कार्यक्रम और अन्य मार्गदर्शन पहल युवा छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अवसर

तलाशने में मदद कर रहे हैं। कल रविवार को डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा छात्रों को उनकी प्रतिभा को जल्दी पहचानने और अनुसंधान के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके भारत के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों को विभिन्न विषयों में जाने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिजिटल परिवर्तन के युग में ऊर्जा सुरक्षा के महत्व पर बोलते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बड़े डेटा केंद्रों जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है और इनमें परमाणु ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्रदान करती है और यह भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक होगी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में परमाणु विज्ञान की बढ़ती भूमिका का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परमाणु चिकित्सा कैंसर और रक्त विकार सहित गंभीर बीमारियों के उपचार में नई संभावनाएं खोल रही है।

सीएम फडणवीस ने नए बिल का किया बचाव, महिलाओं के शोषण को रोकने का भी किया दावा

मुंबई , (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का नया धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन रोकने वाला बिल खास तौर पर महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि कई मामलों मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के लिए बढ़ा–चढ़ाकर पेश कर रहा है। उनका कहना है कि अगर विपक्षी दल इस बिल को ठीक से पढ़ेंगे तो उन्हें इसमें किसी समुदाय के खिलाफ कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ जबरदस्ती, लालच या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया

है। इस बिल में ऐसे धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है जो जबरदस्ती, धोखे, लालच या शादी के बहाने कराए जाते हैं। इस प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शादी का बहाना बनाकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर यह अपराध महिला, नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या अनुसूचित जाति–जनजाति के व्यक्ति के साथ किया जाता है तो सजा और भी सख्त होगी। ऐसे मामलों में सात साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सीएम फडणवीस ने कहा कि कई मामलों में महिलाएं किसी के साथ भागकर शादी कर लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसे हालात में उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, खासकर जब उनके बच्चे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल ऐसे मामलों का समाधान ढूंढने और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।

एशिया संकट पर मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में खोला राज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार को लोकसभा को पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या और संसदीय बजट सत्र के छठे दिन वापस लौटे भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में जानकारी दी। नायडू ने बताया कि भारतीय विमानन कंपनियों ने कुल 4335 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं, जबकि विदेशी विमानन कंपनियों ने 1187 उड़ानें रद्द की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने 4335 उड़ानें रद्द की हैं, जबकि विदेशी विमानन कंपनियों ने 1187 उड़ानें रद्द की हैं। सबसे पहले हमें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अगर हवाई क्षेत्र ही बंद है, तो हमें इस क्षेत्र में उड़ान भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नायडू ने आगे बताया कि पश्चिम एशिया में तनाव के इस दौर में लगभग 2,197,80 लोगों ने यात्रा की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारा नागरिक उड्डयन विभाग और विमानन विभाग वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए हवाई क्षेत्र का खुलना आवश्यक है, जो अभी भी कई क्षेत्रों में संभव नहीं है। इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय पश्चिम एशिया क्षेत्र में उत्पन्न हो रही स्थिति और भारत तथा इस क्षेत्र के देशों के बीच हवाई यात्रा पर इसके प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिचालन समायोजन कर रही हैं।

ओडिशा के राज्यपाल और सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ओडिशा के राज्यपाल कंभमपति ने बताया कि उन्होंने पीएम को ओडिशा में चल रहे विकास कार्यक्रमों, विभिन्न क्षेत्रों में हो रही निरंतर प्रगति के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने पीएम मोदी संग मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्श्आज मुझे नई दिल्ली स्थित संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उन्हें ओडिशा में चल रहे विकास कार्यक्रमों, विभिन्न क्षेत्रों में हो रही निरंतर प्रगति और विकसित ओडिशा और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य के विकास को और गति देने के लिए जारी प्रयासों के बारे में जानकारी दी।श्श इससे पहले ओडिशा के राज्यपाल ने कटक स्थित एक अस्पताल में लगी आग में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, श्श्कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में हुई भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत स्तब्ध हूं। मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उनका उपचार जारी है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।श्श इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्श्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।श्श उन्होंने आगे बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं राज्य की प्रगति से अवगत कराया।

सादगी व शालीनता के चलते आज भी लोगो के दिलों मे है स्वर्गीय राम चन्द्र लाल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। अपने सादगी तथा शालीनता के साथ–साथ समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा जल निगम मे महत्वपूर्ण पद से रिटायर्ड स्वर्गीय रामचंद्र लाल आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।बताते चलें कि जिले के थाना हैदरगंज क्षेत्र के चौबेपुर (जाना बाजार) निवासी राम चन्द्र लाल श्रीवास्तव जहां एक ओर सरकारी नौकरी करते हुए अपने सादगी व व्यवहार के चलते उनका सम्मान अधिकारी से लेकर सभी कर्मचारी करते थे।पैतृक गांव चौबेपुर जाना बाजार में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों तथा अयोध्या शहर में भी उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य के चलते सामाजिक कार्य के चलते लोग उन्हें आज भी याद करते हैं।उनका देहांत आज के दिन 17 मार्च 2014 को दोपहर एक बजे होली के दिन कोतवाली

नगर के अश्वनीपुरम कालोनी में स्थित उनके आवास पर हो गया था।परंतु आज भी समाज में उनके द्वारा किये गये कार्यो की चर्चा समाज में होती है।इसका पता इसी बात से चलता है कि अभी भी जब भी कोई इनके विभाग जल निगम द्वितीय निर्माण शाखा में जाता है या फिर इनके पैतृक गांव चौबेपुर जाना बाजार जाता है तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि जो बात बाबू राम चंद्र लाल में रही वह किसी में नहीं।सूत्रों के मुताबिक जिस दिन इनकी मृत्यु होली के ठीक दोपहर 1रू00 बजे इनके निवास अश्वनी पुरम कॉलोनी में हुई उसी समय लोगों ने एक ही वाक्य कहा कि बाबू राम चंद्र लाल जैसे सामाजिक प्राणी क्षेत्र में कभी–कभी ही मिलते हैं मालूम हो कि राम चंद्र लाल श्रीवास्तव का जन्म अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज क्षेत्र के चौबेपुर जाना बाजार में एक कायस्थ परिवार में हुआ था।इनके पिता जी स्वर्गीय धर्म किशोर लाल श्रीवास्तव वायुसेना विभाग में कार्यरत रहे और इनकी माता जगपति श्रीवास्तव एक ग्रहणी के रूप में भूमिका निभाई।रामचंद्र लाल शुरू से ही जहां एक ओर अपने पैतृक गांव व आसपास में अपने सामाजिक कार्यों के चलते चर्चा में रहे।उन्होने जल निगम में नौकरी किया और वर्ष 2005 में अयोध्या जनपद में स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम द्वितीय निर्माण शाखा रिटायर्ड हुये।उसके बाद वे गाँव के लोगो के कहने पर चुनाव लडा और जीते भी।इनकी मृत्यु की खबर सुनते ही 14 मार्च 2014 को जल निगम विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक गए राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक लोग उनके शहर स्थित अश्विनी पुरम आवास पर तथा पैतृक गांव चौबेपुर में जाकर शोक प्रकट किया। लहर दौड़ पड़ी।आज भी इनके पैतृक गांव के लोग और जल निगम विभाग में इनके समय में कार्यरत रहे कर्मचारी यही बात कहते हैं कि जो शालीनता व सादगी बाबू राम चंद्र लाल में रही वह काबिले तारीफ रही।जिसके चलते आज भी लोग इन्हें इनको याद करते हैं।उनके पुण्यतिथि पर उनके परिवार के सदस्य आज भी गरीबों को निशुल्क फल सहित अन्य सामग्रियों को वितरित करते हैं लेकिन उनके सादगी सरल स्वभाव के चलते सोशल मीडिया समाचार पत्रों में तस्वीर नहीं खिंचवाते।

संपादकीय

अमेरिका की बेपरवाही की मिसाल

भारत के अतिथि जहाज को भारतीय जल क्षेत्र के करीब डुबो देना भारत की प्रतिष्ठा के प्रति अमेरिका की बेपरवाही की मिसाल है। इसलिए इस घटना पर भारत को औपचारिक विरोध एवं आपत्ति अवश्य दर्ज करानी चाहिए। ईरान पर अमेरिका– इजराइल के हमले से पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध की आंच बुधवार को भारत तक पहुंच गई, जब भारतीय जलसीमा के करीब ईरान के जहाज इरिस देना को अमेरिका ने डुबो दिया। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीटर हेगसेट ने इसे अपने देश की एक बड़ी सैन्य सफलता के रूप में पेश कर इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहने दिया कि ये कार्रवाई योजनाबद्ध ढंग से की गई। अमेरिका ने ऐसा करने को सोचा, यह भारत के प्रति उसके तौहीनी नजरिए का परिचायक है। आखिर वो जहाज भारतीय नौसेना के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा कार्यक्रम– मिलन– में भाग लेने भारत के आमंत्रण पर आया था। विशाखपत्तमन में इस कार्यक्रम में भाग लेकर वह लौट रहा था। ईरान ने कहा है कि चूंकि जहाज युद्ध से बाहर के क्षेत्र से गुजर रहा था, अतरू उसकी हथियार प्रणालियों को ष्सुरक्षित एवं निष्क्रियष मोड में रखा गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है– श्हम मान कर चल रहे थे कि हम दोस्ताना जल क्षेत्र में हैं, अतरू जहाज पर सवार अधिकांश लोग समारोहों में भाग लेने वाले गैर लड़ाकू कर्मचारी थे।य डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऐसे जहाज पर हमला करने को सोचा, यह तमाम अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मर्यादाओं को ठेंका दिखाने के उसके नजरिए मेल खाता है। मगर ऐसा भारत के अतिथि जहाज के साथ भारतीय जल क्षेत्र के करीब करना भारत की चिंताओं के प्रति उसकी असंवेदनशीलता की भी मिसाल है। इसलिए इस घटना पर भारत को औपचारिक विरोध एवं आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। दुनिया में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त खुद अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहना होता है। वेनेजुएला और ईरान के मामलों में अंतरराष्ट्रीय नियमों के पक्ष में आवाज ना उठा कर भारत ने पहले ही अपनी अंतरराष्ट्रीय हैसियत की अनदेखी की है। मगर अब बात सैद्धांतिक रुख तय करने की नहीं, बल्कि अपने मामले में बोलने की है। कम–से–कम यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि अमेरिका अपने युद्ध की आंच हम तक पहुंचाए। भारत के क्षितिज पर वैसे ही अमेरिकी युद्ध के आर्थिक दुष्परिणामों का अंदेशा सघन होता जा रहा है।

भारत ने किस प्रकार अपनी ऊर्जा प्रणाली को गतिशील बनाया

आम तौर पर, संरचनात्मक ऊर्जा परिवर्तन शायद ही कभी आरामदायक समय के दौरान होते हैं। वे तब होते हैं जब किसी संकट की लंबे समय तक अनदेखी की जाती है और उसके प्रति निष्क्रिय भाव रखा जाता है। यद्यपि, पिछले 11 वर्षों के दौरान, मोदी सरकार ने इसके विपरीत काम किया है। इसने ऊर्जा क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन किए, तब भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं थीं। इसने भारत को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधानों को सहन करने के प्रति अधिक क्षमता निर्माण में सक्षम बनाया। मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन का विस्तार करके, नए ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन का प्रबंधन करके और आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाकर, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बाहरी झटकों का सामना करने में देश को अधिक सक्षम बना दिया है। भारत के लिए इस समस्या का समाधान करने का मार्ग कभी भी मुश्किल नहीं था। आवश्यकता थी, इसे लगातार आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की। पिछले एक दशक में, मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं पर बने रहने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने खुद को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाया है, जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थी। इसकी कार्यनीति तीन स्तंभों पर टिकी हुई थी और प्रत्येक ने सरकार से एक अलग तरह की प्रतिबद्धता की मांग की। पहले कार्यनीति घरेलू उत्पादन की थी। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने की कार्यप्रणाली 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ हुई थी। फिर भी कई वर्षों तक, भारत ने कोई प्रगति नहीं की और इथेनॉल उत्पादन स्थिर रहा। 2014 के बाद ही व्यापक सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से, भारत इस पहल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हुआ। मोदी सरकार के तहत, देश ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की एक श्रृंखला आरंभ की। इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत शुरू में 2030 के लिए पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि, 2020 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस लक्ष्य को 2025 तक विस्तारित कर दिया, क्योंकि इसने भू–राजनीतिक झटकों की स्थिति में ऊर्जा आयात के प्रति देश की निर्बलता को कम करने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। प्रयासों और नीतिगत फोकस के परिणामस्वरूप, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग 2014 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 20 प्रतिशत हो गया, जो 11 वर्षों में 13 गुना वृद्धि है। इथेनॉल उत्पादन 2014 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर जून 2025 तक 661.1 करोड़ लीटर हो गया। 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम अब सालाना लगभग 44 मिलियन बैरल कच्चे तेल को विस्थापित करता है। दूसरी कार्यनीति सही तरीके से ऊर्जा परिवर्तन करने से संबंधित थी। मोदी सरकार ने सभी स्तरों पर देश के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग के विकास का समर्थन किया। इसने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में शत–प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी, जिसने पिछले चार वर्षों में एफडीआई में 36 बिलियन डॉलर को आकर्षित किया है। प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गईं। भारत में (हाइब्रिड) ईवी का फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (फेम ढ्ढ) 2015 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी को अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे इस क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके। योजना के पहले चरण में, लगभग 2.78 लाख ईवी जोड़े गए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 59 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हुई। फेम इंडिया योजना के परिणाम और अनुभव के आधार पर, फेम का दूसरा चरण 2019 में आरंभ किया गया। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर अग्रिम मूल्य में कटौती के माध्यम से उपभोक्ताओं (खरीदारोंध्अंतिम उपयोगकर्ताओं) को प्रोत्साहन और रियायतें प्रदान की गईं, जिससे इसे व्यापक स्तर पर अपनाने की सुविधा मिली। इस पहल ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए अधिक किफायती और सुलभ बना दिया, जिससे उन्हें अपनाने में तेजी लाने में मदद मिली। इस योजना ने 16 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर सब्सिडी दी, जिससे 42.9 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, इस पहल के परिणामस्वरूप, 2019–20 की तुलना में 2023–24 में भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 9.7 गुना वृद्धि हुई। वर्तमान में, भारत के ईवी बाजार में 2025–2026 में तेजी देखी जा रही है, जिसकी बिक्री 2.3 मिलियन यूनिट (कुल वाहन पंजीकरण का लगभग 8 प्रतिशत) तक पहुंच गई है। ईवी और नवीकरणीय ऊर्जा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में इस परिवर्तन में निर्भरता से जुड़ा जोखिम भी है। खनिज निर्भरता की जगह तेल निर्भरता के लिए बदलाव से पूर्ण ऊर्जा सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। इस निर्बलता को दूर करने के लिए, मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए श्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशनश आरंभ किया।

कौन जीतेगा चुनावी महाभारत बंगाल में होगा बदलाव

नीरज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच एक और बड़े मुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि वामपंथ अपने आखिरी किले को बचाने की जंग लड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की सत्ता का सवाल नहीं हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के रूप में उभर रहे हैं। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार की रणनीति के साथ मैदान में है, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने की आखिरी बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। देखा जाये तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हुए कई विधानसभा चुनावों ने यह संकेत दिया कि भाजपा अभी भी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे मजबूत ताकत बनी हुई है। विपक्ष को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन के बाद उसका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन बाद के चुनावों में भाजपा ने अपनी पकड़ बनाए रखी। अब पांच राज्यों में हो चुका चुनावी शंखनाद का दौर यह तय करेगा कि क्या भाजपा उन राज्यों में भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है जहां अब तक उसे सत्ता नहीं मिली है। देखा जाये तो इन चुनावों की घोषणा ऐसे समय हुई है जब विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत रूप से तथा एनडीए सरकार पर कई मुद्दों को लेकर लगातार हमला कर रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता, पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में इन चुनावों को जनता के वास्तविक राजनीतिक मूड की परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा इस चुनावी दौर में असम में सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ उतर रही है। 2016 से राज्य की सत्ता में मौजूद भाजपा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में खुद को मजबूत स्थिति में मान रही है। पार्टी ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और स्थानीय पहचान के मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है, जिससे चुनावी वातावरण और अधिक तीखा हो गया है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अब तक सत्ता से दूर रही है, लेकिन इस बार वह पूरी ताकत के साथ अपनी राजनीतिक उपस्थिति को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। इन राज्यों में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दल हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भाजपा के सबसे मुखर विरोधियों में शामिल हैं और दोनों ही नेता इस चुनावी मुकाबले में सीधे भाजपा के निशाने पर हैं। हम आपको बता दें कि चारों राज्यों में भाजपा केवल असम में सत्ता में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वह सत्तारुढ़ गठबंधन का हिस्सा है। असम के बाद पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है, जहां वह तृणमूल कांग्रेस को सीधी चुनौती दे रही है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा ने अन्नाद्रमुक के नेतृत्व में एक व्यापक गठबंधन तैयार कर द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे को घेरने की रणनीति बनाई है। केरल का चुनाव अलग मायने रखता है क्योंकि यहां परंपरागत रूप से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ही मुख्य मुकाबले में रहे हैं। लेकिन पिछले चुनावों में भाजपा को करीब 17 प्रतिशत मत मिलने के बाद उसे यहां एक प्रभावशाली कारक के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में यह चुनाव वामपंथ के लिए अपने आखिरी मजबूत किले को बचाने की चुनौती भी बन गया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान की कमान संभालते हुए इन सभी राज्यों में लगातार दौरे और रैलियां की हैं। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ राजनीतिक संदेश देने की रणनीति अपनाते हुए उन्होंने खास तौर पर पश्चिम बंगाल में अपने हमलों को और अधिक तीखा किया। कोलकाता में आयोजित रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनकी राजनीति राज्य में तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा देती है। भाजपा का दावा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों ने राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण को मजबूत किया है और इससे उसे चुनाव में फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी 2011 से लगातार सत्ता में हैं और उन्होंने कई बार भाजपा की चुनौती को रोकने में सफलता हासिल की है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। इसके बाद हुए चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 38 से 39 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा है, जिससे पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वह ममता बनर्जी के किले में बड़ी सेंध लगा सकती है। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में लगातार कमजोर होती जा रही कांग्रेस अब इन चुनावों के जरिये अपने राजनीतिक अस्तित्व को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि केरल में जीत उसके लिए नई राजनीतिक ऊर्जा लेकर आ सकती है। असम में कांग्रेस ने गौरव गोगोई जैसे अपेक्षाकृत युवा चेहरे को आगे कर नई रणनीति अपनाई है। पार्टी का लक्ष्य कम से कम इतना प्रदर्शन करना है कि यह धारणा टूट सके कि असम पूरी तरह भाजपा का गढ़ बन चुका है। तमिलनाडु में कांग्रेस द्रमुक के साथ गठबंधन में है, हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती मतभेद भी सामने आए। वहीं अभिनेता विजय की नई पार्टी के उभार ने चुनावी समीकरण को और जटिल बना दिया है, जिससे तीन कोणीय मुकाबले की संभावना बन रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पिछले चुनाव में पार्टी को शून्य सीट और केवल तीन प्रतिशत मत मिले थे। इस बार उसका लक्ष्य कम से कम पंद्रह प्रतिशत मत हासिल कर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को फिर से स्थापित करना है। कुल मिलाकर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के चुनाव केवल क्षेत्रीय सत्ता की लड़ाई नहीं हैं। यह चुनाव इस बात का संकेत भी देंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का राजनीतिक विस्तार जारी रहेगा या राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष कोई नया राजनीतिक संतुलन स्थापित कर पाएगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले महीनों में यह चुनावी संघर्ष भारतीय राजनीति के सबसे तीखे मुकाबलों में से एक बन सकता है।

अमेरिकी कार्रवाई के बाद गड़बड़ाई विश्व व्यवस्था

उमेश

दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ अपवादों को छोड़ दें तो दुनिया ने सभ्य होने की तरफ लगातार कदम बढ़ाए। लेकिन इक्कीसवीं सदी का चौथाई हिस्सा बीतने के बाद लग रहा है कि एक बार फिर दुनिया आधुनिकता की चादर लपेटे मध्य युगीन बर्बरता की ओर बढ़ रही है। 28 फरवरी, 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद ऐसी सोच वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला रूहोल्लाह मुसावी खोमैनी समेत कई सैन्य अधिकारियों की मौत ने दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। दुनिया के कमजोर देश एक बार फिर आशंकित हो उठे हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि अमेरिका के खिलाफ अगर उन्होंने नीतियां अपनाईं तो हो सकता है कि अमेरिका अपने तरीके से योजना बनाकर उस पर हमला कर दे। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए जिन कारणों को गिनाया है, उनमें सबसे प्रमुख कारण है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकना, ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना और वहां की मौजूदा शासन व्यवस्था को बदलना है। अमेरिका ने तर्क दिया है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के करीब था, जो दुनिया और क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए एक ष्अस्वीकार्य सुरक्षा खतराष है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को त्यागने के हर अवसर को ठुकरा दिया था। ट्रंप का यह भी कहना है कि उसके श्ऑपरेशन एपिक फ्यूरीश का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं और नौसैनिक संपत्तियों को पूरी तरह नष्ट करना है। यह ठीक है कि अयातुल्ला खोमैनी की अगुआई वाले ईरान में इस्लामिक शासन व्यवस्था काम कर रही है, जिसे उसके नागरिकों के बड़े वर्ग का समर्थन हासिल नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईरान की संप्रभुता को चोट पहुंचाई जाए। अमेरिका ने वही किया है। अगर ईरान की जनता अयातुल्ला खोमैनी के शासन को खत्म करती तो और बात होती, लेकिन अमेरिकी हमले में खोमैनी का मारा जाना दूसरे तरह की बात है। इससे आने वाले दिनों में कई खतरे उत्पन्न होंगे। ईरान पर हमले के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ दुनिया में क्रोध पनपे। यह भी हो सकता है कि आतंकी घटनाएं बढ़ें। गुरिल्ला युद्ध और ईरान समर्थित ताकतों द्वारा आतंकवाद के मुखौटे में अमेरिका और उसके समर्थकों को निशाना बनाया जाए। इससे दुनिया की चिंताएं बढ़ना अस्वाभाविक नहीं है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों का हालिया इतिहास बताता है कि उनका घोषित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। नौ सितंबर 2011 को न्यूयार्क के ट्विन टॉवर पर हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अफगानिस्तान स्थित तालिबान और अलकायदा पर कार्रवाई की थी, उस अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन फिर से स्थापित हो चुका है। अफगानिस्तान को छोड़कर भागने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति रहते जो बाइडेन ने लिया था। अफगानिस्तानी तालिबान पर हमले का एक मकसद वहां लोकतंत्र की स्थापना थी, लेकिन अब वहां तालिबान का इस्लामी शासन है और अमेरिका किनारे है। दिलचस्प यह है कि अफगानिस्ता के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस पाकिस्तान ने अमेरिका को सहयोग दिया था, वह पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से जूझ रहा है। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य कार्रवाई शुरू की। उसका बहाना इराक के पास व्यापक जनसंहार के रासायनिक हथियार होने को बनाया गया। दिलचस्प यह है कि इराक में सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हो गया। तीस दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर अमेरिका समर्थित न्याय तंत्र के जरिए लटका दिया गया, लेकिन इराक में अब तक ना तो लोकतंत्र आ पाया है और न ही शांति। कुछ इसी तरह साल 2011 में लीबिया में अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप किया। तब अमेरिका का उद्देश्य लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ हुए नागरिक विद्रोह को समर्थन देकर लीबिया में लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को जरिया बनाया गया। इसके बाद 19 मार्च 2011 को अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ मिलकर हवाई हमले और मिसाइल हमले शुरू किए। तब से लेकर अब तक अमेरिका में कार्रवाई जारी है। अमेरिकी विशेष बलों ने बेंगाजी में 2012 के लीबिया के अमेरिकी राजनयिक मिशन पर हमले के आरोपी अहमद अबू खट्टाला को गिरफ्तार किया। इसके बाद अमेरिका ने 2015 से लेकर 2019 के बाद तक आईएसआईएस और अल–कायदा के खिलाफ ड्रोन और हवाई हमले जारी रखे। जबकि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बीच लीबिया के ही लोगों के हाथों तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी 20 अक्टूबर 2011 को मारे जा चुके थे। भीड़ ने उन्हें उनके गृह नगर सिर्त में पकड़ा गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। तब से लेकर लीबिया अब भी जल रहा है और वहां शांति और लोकतंत्र अब तक इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका की शह पर सीरिया के शासक के खिलाफ बशर अल–असद के शासन के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सीरिया में तेरह वर्षों तक खूनी गृहयुद्ध चलता रहा। इसके बाद हार कर सात दिसंबर 2024 को विद्रोही ताकतों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया और बशर अल–असद के शासन का पतन हो गया। तब से लेकर सीरिया जल रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के शासक निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने तीन जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया। तब से वे अमेरिकी कैद में हैं और वहां नया शासन स्थापित हो गया है। अमेरिका दावा करता है कि वह लोकतांत्रिक देश है। वह पूरी दुनिया में अपनी तरह लोकतंत्र स्थापित करने का दावा करता है। लेकिन जहां भी वह कार्रवाई करता है, वहां लोकतंत्र आते हुए नहीं दिखता। ईरान में भी कुछ वैसा ही हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ विश्व के बड़े हिस्से में क्षोभ है। ट्रंप के दौर में ऐसी कार्रवाइयों से विश्व आर्डर गड़बड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ किनारे बैठ घटनाओं को होते देखभर रहा है। अमेरिका की निगाह बहुत पहले से ईरान पर है। भूराजनीतिक मामलों के कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान पर अमेरिकी हमला चीन की ताकत को रोकने की कोशिश भी है। इसकी वजह यह है कि चीन अपने तेल का तकरीबन नब्बे प्रतिशत हिस्सा ईरान से ही आयात करता रहा है। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा है। चीन ने अपने दफ्तरी कामकाज में कटौती करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों में तो सरकारी दफ्तरों के लिए काम करने वाली गाड़ियों की संख्या को आधा कर दिया गया है और वहां दफ्तरों को हफ्ते में सिर्फ चार दिन खोलने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही वहां स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारत में भी युद्ध का असर दिखने लगा है। सरकार ने यहां पच्चीस दिनों बाद ही दूसरा एलपीजी सिलिंडर बुक करने का नियम लागू कर दिया है। भारत के सॉफ्टवेयर शहर बेंगलुरू के पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के खाने में कटौती के नोटिस वहां रह रहे युवाओं को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां घरेलू गैस की कमी हो गई है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी लोकतंत्र को असली मतदाताओं का नाम काटने से खतरा

नीलोत्पल

बसु श्भारत के विचारश को आगे बढ़ाना ही संविधान द्वारा ईसीआई को सौंपा गया मुख्य कार्य था। दुर्भाग्य से, श्भारत के विचारश के लिए मौजूदा खतरा ठीक इसी जगह से पैदा हो रहा है। इस खतरे के मूल स्रोत को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। यह श्हिंदुत्वश का विचार है जो नागरिकों के बीच उनकी अलग–अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करता है। भारत का विचार सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा द्वारा बुनी गई काल्पनिक कहानियों से नहीं बना था। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहाए गए खून और पसीने से आकार मिला था। जाहिर है, इस विचार ने एक अलग ही कार्यप्रणाली तय की, जिसने 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए संविधान के बुनियादी स्तंभों को बनाने में योगदान दिया। बुनियादी बातें क्या थीं? आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता और उपनिवेशवाद से मुक्ति की ओर बढ़ना स्वतंत्रता संग्राम का ही एक स्वाभाविक विस्तार था। इसे धर्मनिरपेक्ष होना था, ताकि लोगों को अपनी पसंद का धर्म मानने की आजादी और समानता मिल सके। इसे लोकतांत्रिक होना था, जिसके बिना कमजोर और ताकतवर लोगों के बीच की गहरी खाई, और धन व अवसरों में मौजूद भारी असमानता को पाटा नहीं जा सकता था। इसे संघीय होना था, ताकि कई राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, भाषाओं, खान–पान और पहनावे की महान विविधता को सुरक्षित रखा जा सके। वह एक ऐसी विविधता थी जिसे हिंदुत्व द्वारा अपनाई जाने वाली एकध्रुवीय, एक–आयामी और संकीर्ण सोच के जरिए न तो समझा जा सकता था और न ही सुलझाया जा सकता था।जाहिर है, भारत का जो विचार संविधान ने स्थापित किया, वह किसी नव–फासीवादी कार्यप्रणाली पर नहीं चल सकता था। भारत का विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि अलग–अलग तरह के लोग एक समान और साझा नागरिकता के साथ रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा विचार श्सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारश के सिद्धांत पर आधारित होना जरूरी था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी को देश का हिस्सा होने का समान अधिकार मिले। एक श्राष्ट्रीय भाषाश या एक श्राष्ट्रीय धर्मश का विचार संविधान की परिकल्पना से कहीं बाहर था। पश्चिमी लोकतंत्रों की सोच के विपरीत, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनावी लोकतंत्र को ही अपनाया जाना था। लेकिन अगर ऐसा न किया जाता, तो एक साझा और सामूहिक अस्तित्व में भारत की एकता खतरे में पड़ सकती थी। इस कार्यप्रणाली का मुख्य आधार एक मजबूत और संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त श्भारतीय चुनाव आयोगश (ईसीआई)था, जो इस प्रतिनिधि लोकतंत्र को सुनिश्चित करे और उस पर निगरानी रखे। यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि ईसीआई के लिए हर असली नागरिक को वोटर लिस्ट में शामिल करना एक श्कर्तव्यश था, न कि कोई श्उपकारश। इसलिए, मतदाता सूची तैयार करने का काम ईसीआई का था, न कि किसी आम नागरिक का।भारत के विचारश को आगे बढ़ाना ही संविधान द्वारा ईसीआई को सौंपा गया मुख्य कार्य था। दुर्भाग्य से, श्भारत के विचारश के लिए मौजूदा खतरा ठीक इसी जगह से पैदा हो रहा है। इस खतरे के मूल स्रोत को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती। यह श्हिंदुत्वश का विचार है जो नागरिकों के बीच उनकी अलग–अलग धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करता है। भारत में, आरएसएस ठीक वैसे ही करता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन एंड कस्टम्सएनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करने की कोशिश करते हुए करते हैं। व्यावहारिक रूप से कहें तो, अमित शाह ने उन तथाकथित श्घुसपैठियोंश की पहचान करने के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठाई, जो श्दीमकोंश की तरह राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहे हैं!इसलिए, बिना किसी ठोस सुबूत के श्घुसपैठियोंश के मुद्दे को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका अब ईसीआई के तौर–तरीकों में भी शामिल हो गया है। श्पता लगाओ, हटाओ और बाहर निकालोश का नारा

अब ईसीआई के श्विशेष गहन पुनरीक्षणश (एसआईआर) अभियान की एक अलिखित पहचान बन गया है। इस अभियान का मकसद उन नागरिकों के मताधिकार को छीनना है जिन्हें श्दीमकश कहकर बदनाम किया जा रहा है। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि एसआईआर को पूरा करने के लिए जो बहुत कम समय सीमा तय की गई है, वह पूरी तरह से अव्यावहारिक और गलत है। इससे जो नुकसान हुआ है, वह सभी के सामने हैकृखास तौर पर पश्चिम बंगाल में।पश्चिम बंगाल एक सीमावर्ती राज्य है, जहां मुसलमानों की आबादी काफी बड़ी है। अब इन्हीं लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले, कुल मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ थी। जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुए, तो यह संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई। भारी दबाव में आकर, ईसीआई ने अमित शाह के एक अनौपचारिक समर्थक की तरह काम किया और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका चुनाव कानूनों या उनके तहत लिखे गए नियमों में कहीं कोई जिक्र नहीं हैय और उसने श्तार्किक विसंगतिश की एक नई अवधारणा गढ़ ली। यह और कुछ नहीं, बल्कि नामों की वर्तनी में कुछ अंतर, माता–पिता और बच्चों की उम्र में अंतर, और इसी तरह की कुछ अन्य मामूली बातें हैं। यह स्पष्ट रूप से इस बात का सुबूत है कि नागरिकता की अवधारणा को पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश की जा रही है। नतीजतन, लगभग 60 लाख नाम श्निर्णय के अधीनश बताकर रोक दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और महिलाएं शामिल हैं। यह इस बात को भी स्पष्ट रूप से साबित करता है कि शुरुआत में दिए गए इस आश्वासन के विपरीत कि भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ईसीआई को ऐसी विसंगतियों की पहचान करने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना पड़ा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अभी भी टला हुआ है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी यह टिप्पणी करनी पड़ी कि इन तथाकथित विसंगतियों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाने हेतु न्यायिक अधिकारियों को तैनात करना पड़ेगा, जिससे इस तरह के कदम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन तब भी, ईसीआई को एक हलफनामे के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह स्वीकार करना पड़ा कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में अभी एक महीना और लगेगा।

शिक्षकों के हक के लिए होगा बड़ा आंदोलन, मूल्यांकन व्यवस्था पर उठे सवाल – धर्मेंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों का दौरा कर शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के सचिव द्वारा 18 मार्च से एक अप्रैल तक हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 249 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं,

जिनमें जौनपुर भी शामिल है। धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि इन मूल्यांकन केंद्रों पर कार्यरत हजारों शिक्षकों को परीक्षक और अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी एक केंद्र की शिकायत या किसी अन्य कारण से पूरे प्रदेश के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से वंचित करना उचित नहीं है। संगठन ने मांग की कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मूल्यांकन केंद्रों के शिक्षकों को भी परीक्षक के रूप में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन कार्य शुरू होने से दो दिन पहले यानी 16 और 17 मार्च को केवल हस्ताक्षर के लिए शिक्षकों को 50–60 किलोमीटर दूर केंद्रों पर बुलाना तानाशाही रवैये को दर्शाता है। इससे शिक्षकों को भीषण गर्मी में अनावश्यक यात्रा करनी पड़ती है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। संगठन ने मांग की है कि मूल्यांकन से दो दिन पूर्व की उपस्थिति को भी मूल्यांकन ड्यूटी मानते हुए शिक्षकों को उचित पारिश्रमिक दिया जाए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संगठन एक सप्ताह तक परिषद के सचिव के निर्णय का इंतजार करेगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान संगठन के कई जिला पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

हेल्प यू वेलफेयर सोसायटी का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप, 150 मरीजों ने लिया लाभ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर– हेल्प यू वेलफेयर सोसायटी के तत्वाधान में आज जहांगीराबाद, जौनपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगाया गया, जिसमें ठंदतें भ्मकदन न्दपअमतेपजल वाराणसी के अनुभवी व सुविख्यात डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर डा. उमेश कुमार पाण्डेय , डा. नितिन वाजपेयी , डा. शिवेन्द्र सिंह व डा. अनिल पाठक सहित अन्य डॉक्टरों ने भाग लिया। शिविर में डा. शिवेन्द्र सिंह ने कहा कि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होने पर लंबे समय तक दर्द की दवा स्वयं नहीं लेनी

चाहिए। समय रहते डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, ताकि बीमारी का सही कारण पता चल सके और उचित उपचार हो सके। इसी के साथ डा. उमेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि हृदय संबंधी रोगों में समय पर पहचान और उपचार बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को अचानक सीने में तेज दर्द, घबराहट या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत उसे आराम की स्थिति में लिटाकर बिना देर किए नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि समय पर सही उपचार मिल सके। इस शिविर में लगभग 150 मरीजों ने लाभ लिया। साथ ही ब्लड शुगर, बीपी, यूरिन जांच के साथ–साथ मरीजों को निरूशुल्क दवा भी वितरित की गई। कार्यक्रम सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनन्दन सिंह, पूर्व चेयरमैन दिनेश टंडन, सोमेश्वर केशरवानी, समाजसेवी श्री निखिलेश सिंह, सहकार भारती के अध्यक्ष प्रदीप सिंह रिंकू, सरदार मनमोहन सिंह, रश्मी सोनकर, हेमंत सिंह डब्बू दीपक श्रीवास्तव पत्रकार, अंकित श्रीवास्तव, ज्ञान चंद्र अभिषेक पाण्डेय, बृजेश विश्वकर्मा , बृजेश मिश्रा समेत कई संस्थाओ के पदाधिकारियों के साथ–साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम आयोजक यशी इंटरप्राइजेज के अधिष्ठाता देवेश श्रीवास्तव ने सभी गणमान्य लोगो को बुके, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया!

अधिवक्ता की हत्या पर उबाल वकीलों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव, न्यायिक कार्य ठप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,17 मार्च । यूपी के जौनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक अधिवक्ता की पीट–पीटकर हत्या के विरोध में वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट अधिवक्ता समिति के महामंत्री मनोज मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने घटना के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया, जिससे अदालतों का कामकाज प्रभावित रहा। समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने इस हत्याकांड के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि मृतक अधिवक्ता ने कुछ दिन पूर्व अपनी जान को खतरा बताते हुए एसपी से शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहीं, जिसे नजरअंदाज किया गया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखीं। उन्होंने मृतक के परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, केराकत थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया और अधिवक्ताओं को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

यूजीसी नीतियों के समर्थन में नागरिकों का ज्ञापन, उच्च शिक्षा में समान अवसर व पारदर्शिता की उठाई मांग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,17 मार्च । यूपी के जौनपुर में जनपद के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और विधिक संगठनों से जुड़े नागरिकों, छात्रों और अभिभावकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों के समर्थन में राष्ट्रपतिध्राज्यपाल को संबोधित सामूहिक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुनील कुमार भारती को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना बताया गया। ज्ञापन में कहा गया कि समाज के सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना आवश्यक है। इसमें न्लब की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया कि यह संस्था उच्च शिक्षा में मानकों, पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने UGC नीतियों के प्रमुख लाभों को भी रेखांकित किया। पहला, सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर सुनिश्चित करना, जिससे जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश कम हो। दूसरा, आरक्षण और समावेशन की संतुलित व्यवस्था, जिसके तहत SC,ST, OBC और् वर्ग के छात्रों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और आर्थिक सहायता योजनाएं, जो आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करती हैं। चौथा, शिक्षण संस्थानों में फीस नियंत्रण और निगरानी, जिससे निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। अंत में, ज्ञापन में शिक्षा की गुणवत्ता और डिग्री की विश्वसनीयता बनाए रखने में न्लब की भूमिका को अहम बताया गया। हस्ताक्षरकर्ताओं ने इन नीतियों को मजबूत बनाए रखने और प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।

मनरेगा मजदूरी व मानदेय भुगतान को लेकर कांग्रेस का धरना, सरकार पर श्रमिकों की अनदेखी का आरोप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में केंद्र व यूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा मजदूरों की बकाया दिहाड़ी और संविदा कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को जिलाध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विकास भवन में धरना दिया गया और सरकार से तत्काल भुगतान की मांग उठाई गई। धरना–प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में पिछले कई महीनों से मनरेगा मजदूरों को उनके श्रम का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही, मनरेगा कार्यों में लगे लगभग 40 हजार रोजगार सेवकों और संविदा कर्मियों को बीते आठ महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जिलाध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार सिंह ने सरकार पर मजदूरों का हक मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी है, जबकि गरीब और मजदूर वर्ग महंगाई की मार झेल रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि "डबल इंजन" सरकार मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को सौंपा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सत्यवीर सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा ने किया।

लखनऊ जंक्शन पर दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ब्रेल लिपि में स्टेशन का नक्शा लगाया गया

लखनऊ, (संवाददाता)। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में यात्री सुविधाओं के विकास के क्रम में एक नई पहल की गई है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में स्टेशन परिसर का नक्शा लगाया गया है। ब्रेल एक स्पर्श आधारित प्रणाली है, जिसे उंगलियों के पोरों से अक्षरों और प्रतीकों को महसूस कर पढ़ा जाता है। इस नक्शे की सहायता से दृष्टिहीन यात्री बिना किसी सहायता के स्टेशन परिसर में उपलब्ध विभिन्न यात्री सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

जमीनी विवाद में युवक की हत्या, लापरवाही पर थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर ,17 मार्च । यूपी के जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र के गोबरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर युवक की पीट–पीटकर हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में चंदवक थाना प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, हल्का इंचार्ज उपनिरीक्षक सुरेश तिवारी और बीट आरक्षी राजकुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर की गई। एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि कानून–व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। घटना 15 मार्च की रात करीब 9 बजे गोबरा गांव निवासी सच्चिदानंद मिश्रा (पुत्र रामचरन मिश्रा) गांव के पास स्थित एक ट्यूबवेल पर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और लाठी–डंडों से बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) डोभी ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सच्चिदानंद मिश्रा का अपने पड़ोसी विष्णु मिश्रा (पुत्र संतोष मिश्रा) से जमीन और लेन–देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिजनों के अनुसार, 12 मार्च को उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। इस घटना को लेकर पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जौनपुर में 42 मनोनीत सदस्य नियुक्त, स्थानीय निकायों को मिलेगा मजबूती का संबल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,17 मार्च । यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश शासन ने जिले में स्थानीय निकाय प्रशासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए 42 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की है। राज्यपाल की अनुमति के बाद नगर विकास अनुभाग द्वारा जारी सोमवार देर रात जारी सूची में 3 नगर पालिका परिषदों और 9 नगर पंचायतों को शामिल किया गया है। इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने और जन–प्रतिनिधित्व के दायरे के विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है। जिले की तीन नगर पालिका परिषदों में कुल 15 सदस्यों को नामित किया गया है। जौनपुर नगर पालिका परिषद में पंकज श्रीवास्तव , रोहन सिंह, अरविंद गुप्ता, संदीप जायसवाल और राहुल साहू को सदस्य बनाया गया है। मुंगराबादशाहपुर में अरुण कुमार, विजेंद्र जायसवाल, मनोज गुप्ता, राकेश मिश्रा और उमाशंकर गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं शाहगंज नगर पालिका परिषद में सर्वेश चौरसिया, श्याम जी गुप्ता, रूपेश जायसवाल, महेंद्र वर्मा और चंदेश निषाद को मनोनीत किया गया है। इसके अलावा जिले की 9 नगर पंचायतों में 27 सभासदों की नियुक्ति की गई है। जफराबाद, कचगांव, मड़ियाहूं, खेतासराय, केराकत, गौराबादशाहपुर, रामपुर, मछलीशहर और बदलापुर नगर पंचायतों में प्रत्येक से तीन–तीन सदस्यों को नामित किया गया है। जफराबाद से जीरावती मौर्या, दीपिका पाल और राजकुमार राजभर, खेतासराय से शुभम जायसवाल, सोनू बिंद और बिनीता मौर्या तथा बदलापुर से हरिलाल, चंद्रशेखर निगम और सपना शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कचगांव से संतोष कुमार मिश्रा, राजेश पांडेय और काशीनाथ सेठ, केराकत से दिलीप सोनकर, सुरभि और श्यामजी प्रजापति को मनोनीत किया गया है। मड़ियाहूं से धर्मेंद्र सेठ, रोहित जायसवाल और विनोद कुमार, मछलीशहर से सुनील मौर्या, इंदु और आत्मा प्रसाद गुप्ता, रामपुर से शिव शंकर गुप्ता, सौरभ वर्मा और रवि शंकर गुप्ता तथा गौराबादशाहपुर से अजीत चौहान, अजीत सोनकर और संतोष गुप्ता को सभासद बनाया गया है। इन सामाजिक रूप से सक्रिय और अनुभवी सदस्यों के शामिल होने से बोर्ड बैठकों में जनहित के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। नियुक्त सभी सदस्य जल्द ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

मुन्नू खेड़ा रोड पारा में उद्योग व्यापार मंडल की नई इकाई का गठन

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ व्यापार मंडल के अंतर्गत मुन्नू खेड़ा रोड, पारा क्षेत्र में उद्योग व्यापार मंडल की नई इकाई का गठन किया गया। यह गठन अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र के दिशा–निर्देश तथा महामंत्री उमेश शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ।गठन के दौरान सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसमें गंगा प्रसाद यादव को अध्यक्ष और राजभान यादव को वरिष्ठ महामंत्री बनाया गया। हरिराम यादव को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया, जबकि नीरज कुमार रावत, विवेक कुमार मिश्र, रमेश चंद मिश्र और अनूप कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।इसी क्रम में अनिल कुमार यादव, सत्येंद्र यादव, राकेश कुमार तिवारी और रामदेव यादव को महामंत्री बनाया गया। देवेंद्र कुमार आहूजा और जे.एन. सोनकर को वरिष्ठ सचिव तथा चरण सिंह यादव, अरुण कुमार यादव और सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को सचिव का दायित्व सौंपा गया।संगठन को मजबूत बनाने के लिए मोनू यादव को संगठन मंत्री तथा अनिल कुमार भारद्वाज और वीरपाल यादव को प्रचार मंत्री बनाया गया। इसके अतिरिक्त परशुराम पाल, संतोष सिंह और तेजपाल यादव को सलाहकार नियुक्त किया गया। वहीं मंडल के संरक्षक के रूप में सुरेंद्र कुमार पांडे, तेजपाल यादव, अमरेश कुमार यादव, रामगोपाल यादव, आशीष यादव और मनीष कुमार वर्मा को घोषित किया गया।इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए महामंत्री उमेश शर्मा ने कहा कि व्यापार मंडल का उद्देश्य व्यापारियों को एकजुट कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सशक्त मंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि संगठन जितना मजबूत होगा, व्यापारियों की आवाज उतनी ही प्रभावी ढंग से शासन–प्रशासन तक पहुंचेगी।

कांशीराम जयंती पर सपा मुख्यालय सहित प्रदेशभर में कार्यक्रम, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांशीराम की 92वीं जयंती समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित पार्टी कार्यालयों में सादगी के साथ मनाई गई।पार्टी मुख्यालय में कांशीराम के चित्र पर सांसद आर.के. चौधरी, विधानसभा के पूर्व नेता विरोधी दल राम गोविन्द चौधरी तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी सहित पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम भारतीय राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में बहुजनों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने वर्ष 1971 में बामसेफ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तथा दलित समाज में आत्मसम्मान की भावना जगाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने सरकारी सेवाओं में कार्यरत दलित

समाज के सक्षम वर्ग को जोड़कर बहुजन समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया।अखिलेश यादव ने कहा कि कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बीच 1991 में हुए गठबंधन से प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच नए संबंध बने और राज्य में साझा सरकार का गठन हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांशीराम को इटावा से लोकसभा पहुंचाने का काम किया और उन्हें हमेशा सम्मान दिया।उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को पीडीए से मजबूती मिली है। लंबे समय तक इन वर्गों को सामान्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए अधिकारों से एक बड़े तबके को वंचित रखने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब सभी ने एकजुट होकर पीडीए के रास्ते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया है।कार्यक्रम में पूर्व सांसद अरविन्द कुमार सिंह, समाजवादी शिक्षक सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. बी. पाण्डेय, पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव, कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बदहाली की पहचान बनी शहर की वीआईपी कौशलपुरी कालोनी

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। शहर मे सबसे वीवीआईपी कौशलपुरी कॉलोनी मे इस समय चारों ओर समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है।ठेकेदारों और लापरवाह अधिकारियों के चलते कौशलपुरी कॉलोनी के लोग गंभीर समस्याओं से भुगत रहे हैं यहां तक की सड़कों की टूटे होने तथा नालियों व डक्ट के खुले होने के चलते कॉलोनी वासी गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके चलते कॉलोनी वासियो में आक्रोश है। देखा जाए तो राम मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। वही एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के अयोध्या आगमन को लेकर अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है उसी के दूसरी तरफ अयोध्या के सबसे वीवीआईपी कॉलोनी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।देखा जाये तो धर्मनगरी की सबसे प्रतिष्ठित और वीवीआईपी मानी जाने वाली श्कौशलपुरी कॉलोनीश इन दिनों सरकारी सिस्टम की अनदेखी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कॉलोनी की बदहाल सड़कों, अधूरे पड़े निर्माण कार्यों और जलभराव की समस्या ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से कॉलोनी में सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम को बीच में ही लटका दिया गया है। जगह–जगह खोदे गए गड्ढे और बिखरी हुई निर्माण सामग्री आए दिन हादसों को दावत दे रही है। बुजुर्गों और बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है।कौशलपुरी के निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आरोप है कि अधिकारियों की शह पर ही ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। कॉलोनी के मुख्य मार्गों की स्थिति इतनी जर्जर है कि दोपहिया वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो गया है।कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर कहा की प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगे स्थानीय निवासी ने बताया, ष्इसे वीवीआईपी कॉलोनी कहा जाता है, लेकिन सुविधाएं किसी पिछड़े इलाके से भी बदतर हैं।टैक्स हम समय पर भरते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ धूल और गड्ढे मिल रहे हैं।क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य को सही मानकों के साथ पूरा नहीं किया गया और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर 18 मार्च को रात्रि 11:00 बजे से रहेगा रूट डायवर्जेंट

अयोध्या। 19 मार्च को राष्ट्रपति के अयोध्या में आगमनध्कार्यक्रम को लेकर 18 मार्च को रात्रि 23.00 बजे से 19 मार्च को सायं 17.00 बजे अथवा कार्यक्रम समाप्ति तक जनपद अयोध्या की तरफ मालवाहक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, डी0सी0एम0 आदि भारी वाहन का रुट डायवर्जन रहेगा।सुल्तानुपर से आने वाले वाहनों को कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से गन्तव्य हेतु डायवर्जन किया जायेगा।रायबरेली से आने वाले वाहनों को हलियापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से गन्तव्य हेतु डायवर्जन किया जायेगा।आजमगढ़, अम्बेडकरनगर से आने वाले वाहनों को गोहन्ना मोड़ अम्बेडकरनगर से दोस्तपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से गन्तव्य हेतु डायवर्जन किया जायेगा।बाराबंकी की ओर से आने वाले वाहनों को भिटरिया रामसनेही घाट से हैदरगढ़ से पूर्वाचल एक्प्रेस–वे से गन्तव्य हेतु डायवर्जन किया जायेगा।जनपद बस्ती की ओर से आने वाले वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज गोण्डा की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद गोण्डा की ओर से नवाबगंज से आने वाले वाहनों को लकड़मण्डी से लोलपुर से बस्ती की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद गोरखपुर से वाहनों का डायवर्जन–गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेस–वे होकर पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे पर डायवर्जन किया जायेगा।गोरखपुर–संतकबीरनगर–बस्ती से आने वाले वाहनों को फुटहिया चौकी थाना–को0 नगर से कलवारी से टाण्डा से अकबरपुर से दोस्तपुर से पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे पर डायवर्जन किया जायेगा।गोरखपुर की ओर से आने वाने वाहनों का संतकबीर नगर (खलीलाबाद), मंझरिया तिराहा से कटका से मैंनसिर से धनघटा होते हुए बिल्हरघाट फ्लाईओवर से अम्बेडकरनगर, दोस्तपुर से पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे पर डायवर्जन किया जायेगा।गोरखपुर, संतकबीरनगर, बांसी, मेहदावल, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, गोण्डा से आने वाले वाहन जरवल रोड तिराहा से वापस आकर बहराइच की ओर जाकर टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली सीतापुर–लखनऊ मार्ग की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद बलरामपुर, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, से अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाले वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली सीतापुर–लखनऊ मार्ग की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद कानपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कानपुर, उन्नाव, मौरावां, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, चांद सराय से पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे से गोरखपुर की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस–वे से आने वाले वाहनों को मोहान, जुनाबगंज, से मोहनलालगंज से गोसाईगंज से पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे से गोरखपुर की ओर डायवर्जन किया जायेगा।जनपद सीतापुर, शाहजहाँपुर, से आने वाले वाहनों को आई0आई0एम0 रोड दुबग्गा से आलमबाग, नहरिया से शहीदपथ होते हुए अहीमामऊ से होते हुए पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे की ओर डायवर्जन किया जायेगा। समस्त डायवर्जन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लागू रहेगा।

मडियाहूं विद्युत उपकेंद्र में लापरवाही पर कार्रवाई, अवर अभियंता निलंबित

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा के कड़े रुख के बाद जौनपुर जनपद के मडियाहूं विद्युत उपकेंद्र में बड़ी कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता के अनुपस्थित रहने और कार्यालय में अनियमितताएं पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता अनिल पाठक ने अवर अभियंता शहजाद अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित उपखंड अधिकारी सौरभ तिवारी को भी चार्जशीट जारी की गई है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि कई अभिलेख और लॉगशीट सही तरीके से भरे नहीं गए थे तथा जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं थे। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत विभाग जनसेवा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए।

एटीएम कार्ड बदल कर पैसा निकालने वाले गिरोह मे शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अयोध्या।थाना पूरा कलंदर पुलिस ने लोगों को गुमराह करके उनका एटीएम कार्ड बदलकर पैसा निकाल लेने वाले गिरोह मे शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।इसका खुलासा मंगलवार को एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में किया।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी भोले भाले लोगो को अपनी जाल मे फसांकर एटीएम मशीन के अन्दर उनका एटीएम कार्ड बदल कर पैसा निकाल लेते थे। बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोनू पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम रोशना थाना फतेहपुर जनपद गया बिहार,पिंकू पुत्र कुमार विपिन कुमार निवासी सिहना थाना रुपौ जनपद नेवाजा बिहार व मनीष कुमार पुत्र सुनील कुमार संह निवासी ग्राम पाली थाना कउआ कोल जिला नेवादा बिहार प्रान्त के रूप में हुई है।जिसे पिचाशी कुण्ड मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। बताते चलें कि पिछले माह पीड़ित ने थाना पूरा कलंदर में तहरीर के माध्यम से बताया था कि वह 12 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक की ए.टी. एम. मशीन मे पैसा निकालने गया था जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम बदल कर प्रार्थी के खाता से 59600 की अवैध निकासी की गयी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एटीएम मशील मे फेवीक्विक लगा कर वही बगल मे खडे हो जाते थे।जब ग्राहक एटीएम मे आकर अपना एटीएम कार्ड लगाते थे तो उनका एटीएम कार्ड उसमे फंस जाता था तथा एटीएम कार्ड धारक परेशान होता था अभियुक्त उपरोक्त उनका सहयोग करने के नाम पर एटीएम मे जाकर उनका एटीएम बदल कर अन्य किसी एटीएम मे जाकर पैसा निकाल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 199500 रुपया सहित अन्य सामान बरामद किया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम मे शुभम जैन सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय थाना पूराकलन्दर

निरीक्षक मनोज कुमार शर्मा थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या,उ0नि0 अमरेश त्रिपाठी प्रभारी सर्विलान्स सेल अयोध्या,उ0नि0 आलोक श्रीवास्तव थाना पूराकलन्दर, उ0नि0 सूरज कुमार थाना पूराकलन्दर के अलावा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

भारतीय जनता पार्टी देवकाली मंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।भारतीय जनता पार्टी के देवकाली मंडल का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सर्किट हाउस सभागार में सोमवार को प्रारम्भ हुआ।कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति–नीति, संगठन की कार्यप्रणाली तथा जनसेवा की भावना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा को पहुंचाने का कार्य करता है।

प्रशिक्षण शिविर के प्रथम सत्र में पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र ने पार्टी के विकास और इतिहास पर विस्तार से चर्चा की।उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन वर्षों के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर मजबूत हुआ है।उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन की नीतियों और विचारों को जन–जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। द्वितीय सत्र में महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बूथ प्रबंधन विषय पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बूथ संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने–अपने बूथ को मजबूत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश पाण्डेय बादल ने वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उसकी विचारधारा और राष्ट्रवाद की भावना में निहित है, जो कार्यकर्ताओं को निरंतर समाजसेवा के लिए प्रेरित करती है।प्रशिक्षण शिविर में शैलेन्द्र कोरी, प्रतिमा शुक्ला, हेमंत जायसवाल, शशि प्रताप सिंह,आलोक द्विवेदी,अशोका द्विवेदी, शकुंतला गौतम, नीलम सिंह मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मंगलसी सरयू तट पर बच्चों द्वारा चलाया गया स्वच्छता, श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिला गंगा समिति और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून श्जलजश परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में श्वेता साहू जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे अयोध्या के निर्देश के क्रम में जनपद अयोध्या विकासखंड सोहावल ग्राम मंगलसी में पुराने कच्चे घाट पर एक विशेष स्वच्छता अभियान श्रमदान का आयोजन किया गया। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय बच्चों ने अपनी ऊर्जा और उत्साह से सरयू तट की सूरत बदल दी।गंगा प्रहरी और स्थानीय बच्चों ने मिलकर घाट पर बिखरे कूड़े–कचरे और हानिकारक पॉलिथीन को एकत्रित किया। बच्चों ने स्वच्छता की जिम्मेदारी लेते हुए नदी तट को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया एवं नन्हे हाथों ने बड़ा संदेश दिया।कार्यक्रम के दौरान नीरज कुमार सहायक समन्वयक नमामि गंगे ने बताया कि किस प्रकार हमारे छोटे–छोटे प्रयास से नदियों में रहने वाले जीवों के अस्तित्व को बचा सकते हैं। उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी गई। इस अभियान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि नदियों का संरक्षण केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। स्थानीय समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपस्थित लोगों ने बच्चों के इस सराहनीय कार्य की सराहना की और भविष्य में भी सरयू मैया को स्वच्छ रखने का संकल्प दोहराया।इस अवसर पर गंगा प्रहरी विशाल साहू, महिमा, कामेश श्रीवास्तव बाल गंगा प्रहरी सौम्या, माही, आयुष, नंदिनी, मीनाक्षी, आयुषी, कुमुद, तृषा,आराध्या,अनुकल्प,ख्वाहिश साक्षी, गौरी सुमित, संतोष, हिमेश, सनी, अखिलेश, सत्यम आदि उपस्थित रहे।

हरिहरात्मक महायज्ञ के निम्मित ध्वजपूजन आज

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

गड़वार(बलिया)। संत शिरोमणि श्री जंगली बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री जंगली बाबा धाम,गड़वार पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 19मार्च से आचार्य पंडित राहुल उपाध्याय के संयोजकत्व में विद्वान विप्रों द्वारा शतचंडी अनुष्ठान किया जाएगा।जिसकी पूर्णाहुति 27मार्च को रामनवमी को होगी।रामनवमी को ही बाबा श्री का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा व पादुकाभिषेक होगा।साथ ही इसी दिन बाबा के महानिर्वाण शताब्दी पर आयोजित होने वाले हरिहरात्मक महायज्ञ के निम्मित ध्वजपूजन भी धाम परिसर पर किया जाएगा।

2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टीइटी से मुक्त करें – पंकज यादव

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले चल रहे पोस्टकार्ड अभियान के तहत शिक्षकों को टीआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षा से मुक्त करने की मांग तेज हो गई है। इस क्रम में प्रांतीय संयोजक पंकज यादव, ब्लॉक अध्यक्ष रूदौली राजकुमार शर्मा, रविनंदन सिंह, जीशान खान, अनुपम मिश्रा ने जनपद अयोध्या के दर्जनों विद्यालयों का भ्रमण कर शिक्षकों को पोस्टकार्ड अभियान से जोड़ा।पंकज यादव ने कहा कि 1 सितंबर 2025 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से शिक्षक समाज आहत है। सरकार को एनसीटीई के नियमों में शिक्षक हित में संशोधन करना चाहिए।उन्होंने कहा कि किसी भी भर्ती के बाद बीच में नया नियम लागू करना न्यायसंगत नहीं है।टीइटी को लेकर नए नियमों से 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षक पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में टीईटी परीक्षा उनके लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रदेश भर के शिक्षक देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन माननीयों को पोस्टकार्ड भेजकर 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं।अभियान में जिला अध्यक्ष श्याम जी वर्मा, जिला मंत्री डॉ. विवेक चौधरी, सुशीला पांडेय, शीला कुमारी, मंजू पाठक, अमित यादव, आलोक वर्मा, पंचूराम यादव, इंकलाब हैदर खान, राजेश यादव, अरविंद यादव, अवधेश वर्मा, जगदीश, ओमप्रकाश कनौजिया, ओमप्रकाश गौतम सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।

जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय युवा राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाजयुमो प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने किया प्रतिभाग

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह ने जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय युवा राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।कार्यक्रम जर्मनी की प्रसिद्ध संस्था कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था,जिसमें एशिया के विभिन्न देशों से आए युवा राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं ने सहभागिता की।कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, मैनहाइम तथा स्टटगार्ट नगरों का भ्रमण किया और बाडेन–वुर्टेमबर्ग राज्य की चुनावी प्रक्रिया को निकट से समझने का अवसर प्राप्त किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने जमीनी स्तर पर होने वाले चुनाव प्रचार, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं तथा वहां के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के साथ संवाद के माध्यम से जर्मनी की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा।कार्यक्रम के दौरान युवा सहभागिता, संघीय शासन व्यवस्था तथा आधुनिक लोकतंत्र में नेतृत्व की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा हुई। स्टटगार्ट में आयोजित बैठकों में बाडेन–वुर्टेमबर्ग की अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था, विदेश संबंध संस्थान, स्टटगार्ट नगर प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग तथा बाडेन–वुर्टेमबर्ग राज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ भी मंथन हुआ। इन बैठकों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, क्षेत्रीय कूटनीति तथा बाडेन–वुर्टेमबर्ग की एशिया–प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी रणनीति पर विचार–विमर्श किया गया।इस मौके पर हर्षवर्धन सिंह ने भारत और बाडेन–वुर्टेमबर्ग के बीच औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि भारत का मजबूत औद्योगिक तंत्र और कुशल मानव संसाधन, यदि बाडेन–वुर्टेमबर्ग की नवाचार क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल और उन्नत विनिर्माण तकनीक के साथ जुड़े, तो दोनों क्षेत्रों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार बाडेन–वुर्टेमबर्ग राज्य का सहयोग महाराष्ट्र के साथ स्थापित है, उसी प्रकार भविष्य में उत्तर प्रदेश के साथ भी साझेदारी की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक और निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है।समापन पर हर्षवर्धन सिंह ने आयोजक संस्था कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मंच युवा नेताओं को सीखने, संवाद करने और वैश्विक सहयोग की संभावनाओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।उन्होंने कहा कि इस अनुभव से लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने के साथ–साथ वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को भी और अधिक गहराई से जानने का अवसर मिला।

हर्षोल्लास पूर्वक मना यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन का होली मिलन समारोह

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कालेज के मल्टीपरपज हाल मे यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन उ0प्र0, जनपद इकाई अयोध्या का होली मिलन समारोह हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ।समारोह का शुभारम्भ नवनियुक्त साथियों के परिचय से हुई।कार्यक्रम की अध्यक्षता ओंकार नाथ प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज अयोध्या ने किया।कार्यक्रम मे उपस्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या कुसुमलता,पुष्पा सिंह–उप प्रधानाचार्या,राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अयोध्या,सतीश चन्द्र त्रिपाठी–उप निरीक्षक संस्कृत,प्रमोद श्रीवास्तव–आडीटर ने वहां पर उपस्थित पदाधिकारी तथा लोगों को होली की बधाई देते हुए नवनियुक्त कर्मियों को शशांक पाण्डेय–आशुलिपिक व कु0 जान्हवी मिश्रा–कनिष्ठ सहायक के उज्जवल भविष्य हेतु आर्शीवाद प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन हरिवंश वर्मा व विवेक सिंह ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जनपदीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आनन्द यादव, मंत्री नीरज सिंह,उपाध्यक्ष निशा मिश्रा व कोषाध्यक्ष सागर यादव मैं अपनी प्रमुख सहभागिता निभाई।समारोह में आशुतोष पति त्रिपाठी,अजय शुक्ल,सत्येन्द्र नाथ शर्मा, राजेन्द्र यादव, प्रकाश चन्द्र यादव, जनार्दन यादव, कृष्ण कुमार, शत्रुघ्न शुक्ला, हरिकृष्ण श्रीवास्तव, अशोक, संजय श्रीवास्तव, अंजलि चौरसिया, उमाकान्त मिश्रा, अशोक मिश्रा, प्रदीप कुमार, रवीन्द्र नाथ जोशी, सन्तोष श्रीवास्तव, रामबिलास यादव, रोहित, प्रियंका पासवान, अमित तिवारी, गायत्री, सचिन सिंह, मनोज कुमार दूबे, शैलेश स्वरूप,धीरेन्द्र कुमार, अभय मौर्या, सौरभ यादव,नेहा, उपमा,किरन सहित संगठन के पदाधिकारी व शिक्षा विभाग के कर्मचारी भारी संख्या में मौजूद रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।